GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1152
TO BE ANSWERED ON THE 28TH JULY, 2015

JATROPHA PLANTATION

1152. SHRI B.N. CHANDRAPPA:
SHRI D.K. SURESH:

Will the Minister of AGRICULTURE कृषि मंत्री
be pleased to state:

(a) whether Jatropha is being used to produce bio diesel in the country;

(b) if so, the details of the area under Jatropha Plantation and production of bio diesel from Jatropha during the last three years, year/State-wise and

(c) the steps taken by the Government to further encourage Jatropha Plantation in the country to meet the demand of bio diesel in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI MOHANBHAI KUNDARIA)

(a) & (b): Jatropha is not being used to produce bio diesel on a significant scale in the country. This department had undertaken Jatropha plantation up to 2010 for utilization as source of quality planting material for mass multiplication. During the first three years of 11th Five Year Plan period i.e. 2007-08 to 2009-10, plantations of Jatropha was done over an area of 2946 hectares as against the target of 3186 hectares. Under Mini Mission–III of National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) targets of 263 hectares and 434 hectares have been approved under Jatropha plantation for 2014-15 and 2015-16, respectively. Oil marketing companies and their Joint Venture/Limited Liability Partnership have undertaken Jatropha plantation in the States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh. Details of the projects are annexed.

(c): Plantation of Jatropha along with other TBOs is being promoted by this Department under Mini Mission III of National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP). Ministry of New and Renewable Energy had announced a National Policy on Biofuels and its implementation for promotion of biofuels, includes bio diesel. The policy endeavors to facilitate and bring about optimal development and utilization of indigenous biomass feed-stocks for production of bio-fuels.

ANNEXURE

DETAILS PERTAINING TO JATROPHA PLANTATION ACTIVITIES UNDERTAKEN BY PUBLIC SECTOR OIL MARKEITNG COMPANIES AND THEIR JV / LLP

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.

A Joint Venture (JV) Company named "Bharat Renewable Energy Ltd. (BREL)" was formed by three promoters namely M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited, M/s S P Agri Management Services Pvt. Ltd. & M/s Nandan Cleantec Ltd. each having 33.3% share to set up Bio Diesel value Chain in the state of UP. It was proposed that Jatropha / Pongamia plantations would be done by Panchayats in their waste & arid lands utilizing funds from MNREGA scheme. BREL had entered into agreement with the Panchayats to purchase Jatropha seeds at the price to be notified by Government of Uttar Pradesh.

Till 31st March, 2014, total area of about 11,000 acres of Jatropha / Pongamia plantation was completed. However, the yields from such plantations was very poor compared to projections and the mortality rate was high. Independent expert assessed the project to be unviable. Both M/s. S.P. Agri Management Services Pvt. Ltd. & M/s. Nandan Cleantec Ltd. stopped funding the losses of BREL and withdrew from the Management. BREL became defunct and non operational, therefore, it was decided to wind up the Company.

Although purchase window was opened but not a single kg of Jatropha seeds were offered for procurement. BREL has not produced and/or received any Bio-fuel under this agreement.

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and its JV/LLP have carried out Jatropha plantation in the States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh. Details of Plantation area are as under :

State	Plantation (Hectares)						
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Total
Jhabua (MP)*	241	52	--	--	--	--	293
Chhatrisgarh (through JV) **	771	5007	111	--	--	--	5889
Uttar Pradesh (Thorugh LLP)***	--	10	1660	16	132	--	1818
Total (Hectare)	1012	5069	1771	16	132	--	8000

* It was a pilot for plantation of Jatropha on revenue wasteland in Jhabua, Madhya Pradesh. Planatation activities were commenced in 2009-10. The project was closed after completion of project period in 2014.

Contd...2/-

** Indian Oil Corporation Limited (IOCL) and Chhattisgarh State Renewable Energy Development Authority (CREDA) have formed Joint Venture Company namely 'Indian Oil – CREDA Biofuels Ltd.' in 2009 for promotion of energy crop plantation on the revenue wastelands in Chhattisgarh. The JV Company has undertaken Jatropha plantation on 5889 hectare. The low seed yields and high plantation costs have adversely affected the overall viability of the project.

*** Indian Oil Corporation Ltd. and Ruchi Soya Industries Ltd. (RSIL) have formed Limited Liability Partnership (LLP) firm namely 'Indian Oil Ruchi Biofuels LLP' in 2010 to participate in Boi-diesel Value Chain Project of Government of Uttar Pradesh under 'Jeevan Jyoti Yojana (JJY)', a scheme for promotion of energy crop plantation in Uttar Pradesh. As per scheme, Gram Panchayats have undertaken Jatropha plantation on Panchayat wasteland and the role of LLP was limited to facilitate plantation activities and buy back seeds from Gram Panchayat at a support price decided by the Government of Uttar Pradesh. The LLP has facilitated Jatropha plantation on 1818 hectares. However, till date, no seeds have been made available by Gram Panchayats to LLP for Bio-fuel production. The project viability has been adversely affected due to low seed yields.

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. AND ITS JVs

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) has entered into an MoU with Government of Chhattisgarh and Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) on 14th July, 2008 for undertaking energy crop plantation in the State of Chhattisgarh pursuant to which Joint Venture Agreement was signed on 27th September, 2008 to form the Joint Venture company CREDA-HPCL Bio-fuel Ltd. (CHBL) with a mandate to carry out cultivation and maintenance of Jatropha plantation in revenue wastelands.

******

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1152
28 जुलाई, 2015 को उत्तरार्थ

विषय: जट्रोफा पौधरोपण
1152. श्री बी.एन. चन्द्रप्पा:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव डीजल का उत्पादन करने के लिए जट्रोफा का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो जितने क्षेत्र पर जट्रोफा उगाया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है, गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार/राज्य-वार जट्रोफा से जैव ईंधन का कितना उत्पादन किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में जैव डीजल की मांग को पूरा करने के लिए जट्रोफा पौधरोपण को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) एवं (ख): देश में बहुतायत पैमाने पर जैव डीजल उत्पादन के लिए जट्रोफा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस विभाग ने कई गुणा गुणवत्ताप्रद पौधरोपण सामग्रियों के स्रोत के रूप में उपयोगिता के लिए वर्ष 2010 तक जट्रोफा प्लांटेशन निर्धारित किया था। 11वीं पंचवर्षीय अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक 3186 हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 2946 हैक्टेयर के क्षेत्र में जट्रोफा का प्लांट लगाया गया है। राष्ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओपी) के मिनीमिशन-।।। के अधीन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए जट्रोफा प्लांटेशन के अंतर्गत क्रमश: 263 हैक्टेयर और 434 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में तेल विपणन कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यम/लि. देयता भागीदारिता ने जट्रोफा पौधरोपण आरंभ किया है। परियोजना का ब्यौरा संलग्न है।

(ग): राष्ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओपी) के मिनी मिशन-।।। के अंतर्गत इस विभाग द्वारा अन्य टीबीओ के साथ अलग से जट्रोफा के पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीन एवं नव ऊर्जा मंत्रालय ने जैव डीजल सहित जैव ईंधन के सवंर्धन के लिए जैव ईंधन और इसके कार्यान्वयन पर नई नीति की घोषणा की है। इस नीति ने जैव ईंधन के उत्पादन हेतु ईष्टतम विकास और घरेलू जैव चारा भंडारों की उपयोगिता को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है।

संलग्नक

सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों और उनके जेवी/एलएलपी द्वारा निर्धारित जट्रोफा प्लांटेशन कार्यकलापों को सहायता का ब्यौरा

भारत पैट्रोलियम निगम लि.

संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी नामत: "भारत नवीन ऊर्जा लि. (बीआरईएल)" तीन प्रमोटरो नामत: मैसर्स भारत प्रेटोलियम निगम लि. मैसर्स एस.पी. एग्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. एवं मैसर्स नन्दन क्लीटी लि. द्वारा प्रत्येक का 33.3 प्रतिशत अंशदान सहित उत्तर प्रदेश राज्य में जैव डीजल मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए तैयार किया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि पंचायतों द्वारा मनरेगा स्कीम से उनके पास बंजर भूमि और शुष्क भूमि का उपयोग करके निधि हेतु जट्रोफा/पोंगामिया पौधरोपण किया जाएगा। बीआरईएल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मूल्यों पर जट्रोफा बीजों की खरीद के लिए पंचायतों के साथ समझौता किया था।

31 मार्च, 2014 तक जट्रोफा/पोंगामिया पौधरोपण के लगभग 11000 एकड़ के कुल क्षेत्र को पूरा किया गया। तथापि, ऐसे पौधरोपण से होने वाली उपज अनुमान की तुलना में बहुत खराब थी। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने परियोजना की अव्यवहार्यता का आकलन किया है। दोनों परियोजनाओं मैसर्स एसपी एग्री मैनेजमेंट सर्विस प्रा.लि. और मैसर्स नन्दन क्लिनटी की बीआरईएल के घाटे के कारण उनका वित्तपोषण रोक दिया गया और उसे प्रबंधन से निकाल दिया गया। बीआरईएल मृतप्राय और अकार्यात्मक हो गया, अत: कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया।

यद्यपि खरीद विंडों को खुला रखा गया, परंतु खरीद के लिए 1 किलो जट्रोफा बीज का भी प्रस्ताव नहीं आया। बीआरईएल ने इस करार के तहत कोई जैव ईंधन न तो उत्पादित किया और न तो प्राप्त किया।

इंडियन ऑयल निगम लि.

इंडियन ऑयल निगम लि. (आईओसीएल) और इसके जेवी/एलएलपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में जट्रोफा पौधरोपण कराया है। पौधरोपण क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	पौधरोपण (हैक्टेयर)						
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
झबुआ (म.प्र.)*	241	52	--	--	--	--	293
छत्तीसगढ़ (जेवी के माध्यम से)**	771	5007	111	--	--	--	5889
उत्तर प्रदेश (एलएलपी के माध्यम से)***	--	10	1660	16	132	--	1818
कुल (हैक्टेयर)	**1012**	**5069**	**1771**	**16**	**132**	--	**8000**

* यह झबुआ, मध्य प्रदेश में बंजर भूमि राजस्व पर जट्रोफा के पौधरोपण के लिए पाइलट था। पौधरोपण कार्यक्रम 2009-10 में शुरू किया गया था। इस परियोजना को परियोजनावधि 2014 में पूरा होने के बाद बंद कर दिया गया।

** इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) और छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (सीआरईडीए) ने वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ ने राजस्व बंजर भूमि पर ऊर्जा फसल पौधरोपण का संवर्धन करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी 'इंडियन आयल-सीआरईडीए जैव ऊर्जा लि." नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। जेवी कंपनी ने 5889 हैक्टेयर क्षेत्र पर जट्रोफा पौधरोपण कराया है। इस परियोजना की समग्र व्यवहार्यता को कम बीज उपज और अधिक पौधरोपण लागत ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

*** इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. और रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. (आरएसआईएल) ने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा फसल पौधरोपण के संवर्धन के लिए एक स्कीम "जीवन ज्योति योजना (जेजेवाई)" के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की जैव डीजल मूल्य श्रृंखला परियोजना में सहभागी होने के लिए वर्ष 2010 में "भारतीय तेल रूचि जैव ईंधन (एलएलपी)" नामक सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) फार्म का गठन किया गया है। स्कीम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों ने पंचायत की बंजर भूमि पर जट्रोफा पौधरोपण कराया है और एलएलपी की भूमिका पौधरोपण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने तक सीमित थी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ग्राम पंचायत से बीजों को फिर से खरीदना था। एलएलपी ने 1818 हैक्टेयर क्षेत्र पर जट्रोफा पौधरोपण को सुविधाजनक बनाया है। तथापि, आज तक जैव ईंधन उत्पादन के लिए एलएलपी को ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बीज उपलब्ध नहीं कराई गई है। परियोजना की व्यवहार्यता कम बीज उपज के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि. और इसके जेवी

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि. (एचपीसीएल) ने छत्तीसगढ़ राज्य ने ऊर्जा फसल पौधरोपण शुरू करने के लिए 14 जुलाई, 2008 को छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (सीआरईडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसकी सहमति पर 27 सितंबर, 2008 को एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्तार किया गया जिससे कि राजस्व की बंजर भूमि में जट्रोफा पौधरोपण की खेती और रख-रखाव को अनिवार्य करने के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी सीआरईडीए- एचपीसीएल जैव ईंधन लि. (सीएचडीएल) का गठन किया जा सके।

****